indigenous coal. Sir, with regard to his question about the petroleum sector, I would adivse him to address that question to the Minister of Petroleum.

MR. CHAIRMAN: We have spent enough time on this question. Now, Question No. 84.

Harassment of Innocent people while dealing with Militants

*84. SHRI SHARIEF-UD-DIN SHARIQ: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what steps have been taken to stop the crossing of LoC by the militants in J&K and the result thereof;

(b) whether different security agencies have given different number of militants present in the State;

(c) what is the actual number who have crossed the LoC after Kargil incident;

(d) whether there is any direction to the security forces, that while dealing with militants, innocent citizens should not be harassed; and

(e) if so, the reasons for which the reports of harassment of innocent people are coming regularly?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Appropriate measures continue to be taken against infiltration by terrorists. Following are some of such measures:—

(a) T1K: army has been deployed in direct eyeball to eyeball attack with adversary's iroops.

(b) All routes of ingress and infiltration are guarded any patrolled by our troops.

(c) Adequate defensive and counter-infiltration postures have been adopted in dynamic tiers.

(d) Retaliatory fire is brought down upon the Pakistani troops in the event of unprovoked firing by Pakistan, that is often taken recourse to, to provide cover to infiltration attempts.

(e) Continuous operations in the hinterland are carried out by the security forces to neutralise the terrorists who have infiltrated into Jammu & Kashmir.

The army foiled 79 infiltration attempts across the LoC during 1999. 124 terrorists were killed during the infiltration attempts and 36 terrorists were apprehended. 132 weapons were recovered.

All figures regarding infiltration by the terrorists are, for obvious reasons, based on estimates. Army estimates assess that 1650 to 1950 terrorists have infiltrated into Jammu & Kashmir during the post Kargil period.

The security forces are under instructions to observe due caution to ensure that the human rights of innocent citizens are not violated. Regular training is imparted to the troops to make them aware of the human rights issues. Aberrations are severely dealt with.

Many reports on human rights violations by the security forces have been found to be false and as having emanated from the sympathisers of terrorists with the intention of demoralising the security forces.

† श्री शरिफ-उद्दीन शरीकः चेयरमैन सर, मेरे सवाल के सिलसिले में डिफेंस मिनिस्टर साहब का जो जवाब आया है, उसमें इन्होंने कई इकदामात का ज़िक्र किया है कि जम्मू-कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि "कारगिल वार" के बाद जब से आपने ये इकदाम शुरू किए, उसके बाद से इन्फिल्ट्रेशन में कितने फीसदी कमी आई है? वह कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? अगर कम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वह इनफिल्ट्रेशन ज्यादा हुआ है ? अगर कम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वह इनफिल्ट्रेशन ज्यादा हुआ है तो जो इकदाम आपने किए हैं, कहीं ये नाकाम तो नहीं हुए है? एक तो मैं यह पूछना चाहूंगा।

दूसरे, इन्होंने दो तादाद दिए हैं कि इतने मिलिटेंट्स मारे हैं और इतने पकड़े है। After Kargil War जो ओवरआल सिचुएशन हमें लगी, उसके बाद मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट आई हैं जहां किसी ने कहा कि दो हज़ार मिलिटेंट आ गए, किसी ने कहा कि ढाई हज़ार आ गए और कई अखबारों में आ गया कि तीन हज़ार आ गए। तो यह कनफ्यूज़न तो एजेंसियों का है और हमें यकीन है कि इनमें से कोई भी उनको गिन नहीं पाया है। किसी ने टेंट में बैठकर बाहर नंबर लगा दिया कि इतने लोग आए है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि असल में रिपोर्ट क्या है? कितने हज़ार हैं? कम है या ज्यादा है? इस बारे में इन्होंने एक एजेंसी की राय यहां भेजी है लेकिन अखबारात में मुख्यालिफ एजेंसियों की तादाद मुख्तलिफ आई है। कभी तीन हजार आ गया, कभी

† Transliteration of the Speech in Persian Script is available in the Hindi version of the Debates.

चार हजार आ गया, कभी बारह हजार आ गया। इस तरह यह कंफ्यूजन है जो दूर कराना चाहूंगा इनके जरिए से।

तीसरी बात, कई-कई जगह से शिकायतें आती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से , जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आती है, जहां बेगुनाह लोगों को परेशान करने की बात आती है । जब यह कहा जाता है कि"Many reports on human rights violations by the security forces have been found to be false and as having emanated from the sympathisers of terrorists with the intention of demoralising the security forces." यहां हर इंसान पर आप यही आरोप नहीं लगा सकते। कोई आदमी, सिक्योरिटी फोर्स कोई आसमान से उतरी पवित्र चीज़ नहीं है। हमारे बेटे, हमारे भाइयों से भी गलतियां हो सकती है। इस देश की खूबी यह है कि प्राइम मिनिस्टर तक को अदालत में पेश किया जाता है । कानून से बालातर कोई नहीं है। इसी खूबी के अनुसार हम यह चाहेंगे कि वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ओर ध्यान दिया जाए और सिर्फ यह कहना कि उनके हमदर्द फैला रहे हैं, यह बात नहीं है। मैं जनरल पठानकर से बात की थी । लोगों के नोटिस में यह बात आई है।

श्री सभापति9 : आप सवाल खत्म कीजिए। टाइम खत्म हो जाएगा।

श्री शरीफ उद्दीन शरीक : मैं खत्म कर दूंगा। एक तो जनाब यह सवाल था और दूसरा यह कि इस तरह की वाज़ेहिदायत दे दीजिए कि डील करते समय बेगुनाह लोगों को बिना वजह परेशन न किया जाए। ये दो बातें जिन्हें मैं पूछना चाहता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, मैं आपके आखिरी प्रश्न से या इसे आखिरी सप्लीमेंट कहें, से शुरू करना चाहता हूं। जो लिखित जवाब हमने सप्लीमेंट के जरिए दिए हैं, उसमें यह कहा है कि "Many reports on human rights violations by the security forces have been found to be false..." यह है कि इसमें किसी को बचाने की या किसी को कटघरे में रखने की बात नहीं है। मेरे पास, 1993 से लेकर 1999 तक जितने इस प्रकार के आरोप लगा दिए गए, उनकी संख्या है 1,333 । इनमें से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और मंत्रालय के जरिए सेना के पास जो शिकायतें गई, वे हैं 231 इन सारे मामलों की जो जांच हुई उसमें सही आरोप पाए गए 48 और बाकी आरोप सही नहीं पाए गए। इनमें से मैंने 1999 के विशेष आंकड़े निकाले हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं । 1999 में, जो साल अभी खत्म हुआ है, आरोप लगाये गए 107 और इनमें से जांच हो चुकी है 66 की और सही पाए गए 3 और 64 गलत पाए गए। जहां तक सेना की तरफ से नागरिकों के साथ जम्मू एण्ड कश्मीर में जो व्यवहार हो रहा है इसके बारे में जिस तरह की बातें बीच-बीच में उठाने जाती है , छापकर लाई जाती है, उसे लेकर कभी आंदोलन भी चलते हैम उसमें कितना सत्य है यह इन आंकड़ों से मालूम होता है। सभापति जी, माननीय सदस्य ने यह

भी पूछा कि क्या उपाय है, कौन-कौन से तरीके है जिससे लोगों के साथ, नागरिकों के साथ उनके व्यवहार ठीक रहे। सभापति जी, यह मामला अभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था, एक मुकदमें के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, क्या-क्या आदेश दिए जाने चाहिए सेना को, उनके अपने व्यवहार के बारे में, वे आदेश उस विस्तार से कुछ मुद्दों के साथ दिये थे। उनका अमल पूरा-पूरा होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कहीं भी गलत काम होता हो तो जो गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें सजा दी जाती है। 1993 से लेकर 1999 तक की अवधि में सेना के 120 लोगों को सज़ा दी गई और 1999 में तीन लोगों को सज़ा दी गई । इसलिए जहां कहीं कोई गलत काम करता है अथवा आदेश का पालन नहीं करता है, उन पर तत्काल कार्यवाही करने का इंतज़ाम है, आर्मी हैदक्वार्टर्ज़ में ह्यूमेन राइट्स सेल है जो सारी चीजों को मोनिटर करता है। चूंकि सेना की अपनी धरती पर भी परेशानियां है और अगर अपने ही नागरिकों को परेशानी हो दुश्मन से सामना करते हुए तो फिर किसी को भी स्वीकार नहीं हो सकता है। लेकिन जहां कहीं भी गलती होती है या जानबूझ कर के काम किया जाता है और ऐसे अपराध होते हैं वहां सज़ा दी जाती है।

MR. CHAIRMAN: Have you completed your answer?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir,, there are two other parts of this question about infiltration.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

News-item regarding Mid-air crash

*85. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item "Mid-air crash averted on R-Day" appearing in Hindustan Times dated 3.2.2000;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) whether independent inquiries have been conducted into the matter and if so, the findings thereof and the follow-up action taken/ to be taken in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) On 26th January 2000, as part of the Republic day Parade flypast, a formation of three TU-142 M aircraft of Navy was required to